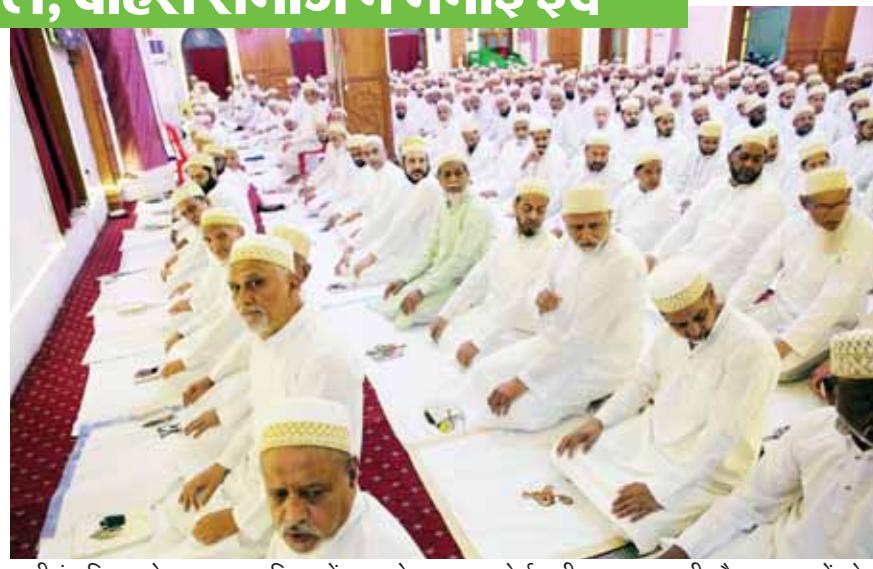




## बकरीद कल, बोहरा समाज ने मनाई ईद



मुस्लिम समाज कल शनिवार को बकरीद का पर्व मनाएगा। जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राजधानी भोपाल कई कई जगहों पर बकरों का गार्ड लगा रहा और कुर्बानी देने के लिए खरीददारों की भी भारी भीड़ देखी गई।



अलीगंज स्थित बोहरा समाज मस्जिद में आज बोहरा समाज ने ईद की नमाज अदा की और एक दूसरों को ईद की बधाई दी। फोटो निर्मल व्यास

आदमपुर खंती में किया जाएगा प्लांट

## कुर्बानी के अवशेष इकट्ठा करेंगी नगर निगम की टीमें

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

राजधानी में ईदुल अजहा (बकरीद) कल 7 जून शनिवार को मनेगी। इसके बाद 3 दिन तक कुर्बानी का सिलसिला चलेगेगा। नगर निगम कुर्बानी के अवशेष इकट्ठा करेगा। जिसे आदमपुर खंती में बने रेडिंग प्लांट पर ले जाया जाएगा। जहां मुर्गा, बिल्डिंगों के लिए दाने बनाए जाएंगे।

नगर निगम ने सभी 21 जून के लिए टीमें भी बनाई हैं। सहायक स्वास्थ्य अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे सभी 85 वार्डों में गढ़िया चलाकर कुर्बानी के अवशेष को इकट्ठा करें। वर्षों, उनके मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। इसे लेकर गुरुवार को महापौर मालती राय ने ईद और स्वच्छता विषय पर बैठक भी की। ऐसा पहली बार होगा, जब रेडिंग

प्लांट में सारा वेस्ट जाएगा और फिर इसके मुर्गा-बिल्डिंगों के लिए दाने बनाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट प्लांट में पशुओं के शब्द या मांस के अपशिष्ट को इकट्ठा किया जाता है। इनमें खाल, चर्बी, हड्डी भी शामिल हैं। प्लांट में शब्द को छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और पिर उच्च तापमान पर पकाया जाता है। सारी प्रोसेस पूरी करने के बाद जानवरों के लिए दान तैयार किए जाते हैं।



### गली-मोहल्लों में जाकर मीटिंग भी कर रहा निगम

कुर्बानी के अवशेषों को इकट्ठा करने के लिए तीन दिन नगर निगम की गढ़िया वार्डों में पहुंचेगी। ताकि, अवशेष को खुले या सार्वजनिक स्थानों पर न फैका जाए। इसके लिए निगमकर्मी गली-मोहल्लों में जाकर बैठकें भी कर रहे हैं।

शामिल हैं। प्लांट में शब्द को छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और पिर उच्च तापमान पर पकाया जाता है। सारी प्रोसेस पूरी करने के बाद जानवरों के लिए दान तैयार किए जाते हैं।

### शुद्धता परीक्षण शिविरों का आयोजन, कल से सांची करेगा दूध का दूध पानी का पानी

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अधीन आ चुके मप्र स्टेट को आपारेटिव डेरी फेडेशन का उत्तराधारी अपनी गुणवत्ता प्रमाणिकता को साकारत करने के लिये कल से मैदान में उत्तर रहा है। संघ में सीईडी प्रतीश जोशी के निवास में % दूध का दूध और पानी का पानी%, अधियान 7 जून से शुरू होगा। इस दौरान सांची ब्रांड के दूध और दूध उत्पादों की शुद्धता की जांच उपभोक्ताओं के सामने होगी। ताकि उपभोक्ता जान सके कि सांची दूध और अन्य उत्पाद किंतु शुद्ध हैं।

कल शनिवार को पहले दिन राजधानी में फैर्चून सिनेचर सोसाइटी और इंडस गार्डन, रोहित नगर में तथा रोहित नगर में इसका शिविर होगा। इसके बाद अलग तरीकों पर सकेत नगर कटारा, सागर रायबेला, सिंग वैली, अग्रत नगर, सेवाए कालोंकरम गुलमोहर, नीरज नगर से लेकर सर्वधर्म कालोनी, लालचाली, संजीव नगर, कोरेंकाजा, पुलिस कंट्रोल रूम और गिरधर परिसर में भी यह अभियान मिला तो विस्तृत रिपोर्ट 48 घंटे में लांचित किया जाएगा।

### उपभोक्ताओं तक चल प्रयोगशाला लेकर पहुंचेगा अमला



#### ऐसे होंगी जांच

अभियान में सांची दूध और दूध उत्पाद जैसे पी, पॉर्न एवं दही का परीक्षण चल प्रयोगशाला के माध्यम से उपभोक्ताओं के समक्ष होगा। जांचों में दूध में फैट, एसएनएफ, प्रीटीन, लैक्टोज, पानी, यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोस, नमक, वेजिटेबल स्टर्टर्च, न्यूलाइजर, ऑयल तथा अमोनियम सल्फेट की सदिगता की जांच की जाएगी। परीक्रम में स्टार्टर तथा दही में स्टार्टर, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया एवं माल्टीज की संदिग्धता का भी परीक्षण होगा। वी गुणवत्ता की जानकारी भी उपभोक्ताओं को तत्काल मिलेगी, यदि वी सदिगत मिला तो विस्तृत रिपोर्ट 48 घंटे में लांचित किया जाएगा।

## पांच मंजिला भवन भी बना पर मार्डन कार्डियक यूनिट का प्रोजेक्ट रद्द

### लेटलतीफी का सीधा खामियाजा दिल के मरीजों को भुगतना पड़ेगा

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

राजधानी में नए इलाके की आवादी का सबसे बड़ा सरकारी चिकित्सा केंद्र जेपी अस्पताल का बहुवर्षीयत 5 मंजिला नया भवन इस महीने की तीस तारीख को अस्पताल प्रशासन की सौंपा जाना तय हो गया है लेकिन अपने उमीद इसलिये पुकार नहीं बयां किया यह तीसरी बार है जब डेल्टालाल तय की गई है, और कहा जा रहा है कि एक बार पिछे भवन अशुद्ध ही मिलने वाला है। इस लेटलतीफी का सीधा खामियाजा उन दिल के मरीजों को भुगतना पड़ेगा जिन्हें सरकारी इलाज की सबसे ज्यादा ज़रूरत है। वहीं स्वास्थ्य महकमे ने अस्पताल में बनने वाली मॉर्डन कार्डियक यूनिट के पूरे प्रोजेक्ट को ही रद्द कर दिया है। जबकि 2023 में विभाग ने जेपी अस्पताल में 30 बेड की एक एडवांस कार्डियक यूनिट बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया था। इसे अप्रैल 2024 तक शुरू किया जाना था, लेकिन बार-बार ब्रोजेक्ट में देरी होती गई और इसके साथ भी ही इसकी लागत भी बढ़ती गई। इस बेहिस्क बदेरी और लागत वृद्धि का नीती यह हुआ कि कैथरेल (दिल से जुड़े और अपरेशन के लिए एक विशेष अपरेशन एप्टर) के लिए जेपी शस्त्रीयों का टेंडर खुलने के बाद भी, इस पूरे प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया।

## जेपी में बन रही रप्ताल बिल्डिंग भी हुई 'जनरल'



### कार्डियक यूनिट की बिल्डिंग बनी, मरीनें भी तय...

जानकारी के मुताबिक इस यूनिट में मॉर्डन कैथ लैब के साथ-साथ दिल की जटिल सर्जरी के लिए जेपी शस्त्रीय उपकरण होने का दावा किया गया था, लेकिन अब यह सब खत्म सा लग रहा है। इस प्रोजेक्ट के रद्द होने से सबसे ज्यादा असर गरीब और जरुरतमंद मरीजों पर होगा। दिल से जुड़ी जांचों और ऑपरेशन, जो सरकारी अस्पताल में बेहद कम या मुक्त में होते हैं, अब उन्हें निजी अस्पतालों में लातोंसे रुपए खर्च करके करवाने पड़ेंगे।

### कार्डियक यूनिट की बिल्डिंग बनी, मरीनें भी तय...

बताया जाता है कि सरकार ने तकनीकी कारण बताकर यहां बनने वाली बहुवर्षीयता सुपर स्पेशलिटी कार्डियक यूनिट का कैथलैब टेंडर निरस्त किया है। यह वही यूनिट थी, जिसके लिए नए अस्पताल भवन के दो फ्लॉर का ब्लॉक तैयार किया है। बावजूद अब यह एजियोग्राफी और एजियोलास्टी की सुविधा शुरू नहीं हो पाएगी। ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जो अपरेशन एप्टर बना है, वहां सामान्य अंपरेशन होंगे। 50 बेड के कार्डियक आईसीयू की जगह सामान्य आईसीयू के मरीज रहेंगे। वहां ट्रैम्पिल, इंको, कलर डॉक्टर जैसे एडवांस टेस्ट भी नहीं हो पाएंगे। उक्तेवनी है कि डिट्री सीएम राजेंद्र शुक्रल ने जनवरी में कहा था कि जेपी हास्पिटल में मार्च 2025 तक कैथ लैब और हृदय अपरायर संबंधी सुविधाओं का कार्य पूरा कर लिया जाएगा तथा 100 विसर्गों की हृदय अपरायर यूनिट स्थापित की जाएगी।

### एम्स और हमीदिया से कम नहीं होगा दबाव

अभी भोपाल में इस वर्क सिर्फ एम्स और हमीदिया ही ऐसे अस्पताल हैं जहां कार्डियक यूनिट है। लेकिन दोनों ही अस्पतालों की बालत यह है कि एक-एक मरीज को ओपीडी में घटों लाइन में लगना पड़ता है। जेपी में अब यूनिट न बनने से जेपी शार्ट और ब्रांट घर्टोंस को निजी अस्पतालों का रुख करना होगा, जहां इलाज का खर्च लातों में पहुंच जाता है। हालांकि जेपी की कार्डियक यूनिट का ब्रोजेक्ट बिना कोई ठोस कारण निरस्त करना सवालिया धोरे में है। अभी जेपी अस्पताल में 400 बेड हैं, और नया भवन के शुरू होने के बाद 240 और बेड जुड़ जाते। इससे कुल संख्या 640 हो सकती थी। हालांकि कहा जा रहा है कि कंसंग है कि संभव है कि सरकार की तरफ से कोई फिर इसके लिये नया भवन लाया जाए।

हिंदूराम नगर, दोपहर मेट्रो।

### भाभा विवि से एमटेक पासआउट निधि का पीएससी में चयन

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

भाभा विश्वविद्यालय की एमटेक वीएलएसआई पासआउट छात्रों की निधि कार्डियक यूनिट की संस्थान से सहायता के निवेदक के रूप में चुना गया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के सीईओ प्रीप



शभर में इस वक्त पानी को लेकर दो तरह की चर्चा है। पहली यह कि देश में मानसून समय पर आ गया है कई राज्यों में बरस रहा है तथा कई राज्यों तक प्री मानसून प्रक्रिटिकटी पहुंच गई है। दूसरी चर्चा का विषय हाल में पाकिस्तान से तनाव के बारे भारत द्वारा चिनाब नदी का पानी रोकना व इसके बाद चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकने की आशंका है। पहले मानसून पर बात करें तो पूर्वोत्तर में यह तबाही मचा रहा है। लोगों का जीवन संकट में है। असम की हालत खराब है। वर्तमान स्थिति का सबसे बड़ा कारण जलवाया परिवर्तन तो ही है, कमज़ोर बुनियादी ढांचा भी है। पूर्वोत्तर के कई राज्य हर बार भरी बारिश का सामना करते हैं। इस दौरान नदियां उफन पड़ती हैं। जर्जर टटबंध पानी के बेंकों को संभाल नहीं पाते। नतीजा यह कि कई जिले जलमग्न हो जाते हैं, जिससे हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। फसलें बर्बाद हो जाती हैं। दरअसल, जंगलों की कटाई, अवैध खनन और अनियोजित शहरीकरण से यह समस्या बढ़ी है। पूर्वोत्तर में आपदा प्रबंधन आज

## सपादकाय

तक मजबूत नहीं बन पाया है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, असमाचल सहित कई राज्य इस भारी भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। पूर्वोत्तर में बरसात के दिनों में यहीं हार बार तस्वीर दिखती है। सवाल है कि बाढ़ से बचाव के लिए राज्य सरकरें पहले से तैयारी कर्तों नहीं करतीं। जलवायु विशेषज्ञों ने आगाहि किया है कि अगर जलवायु अनुकूल रणनीति और योजनाएं नहीं बनाई गईं, तो भविष्य में बारिश बड़पैमाने पर तबाही ला सकती है। मौसम वैज्ञानिक पहले से ही बताते रहे हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की संरचना नाजुक है। ऐसे में, जल निकासी का व्यापक प्रबंधन न होने से मूसलाधार बारिश के दौरान जल प्रवाह को संभालना मुश्किल होता है उण्णकटिबंधीय मौसम विभाग की रपट

बताती है कि वर्ष 2000 से 2020 के बीच मेघालय, असमाचल और असम में 33 फीसद बारिश बढ़ी है। ऐसे में आपदा प्रबंधन से जुड़े योजनाकारों और मौसम विज्ञानियों को बारिश में आई तीव्रता और मौसम के बदलते भिजाज को समझना होगा। प्राकृतिक आपदा के कारण नागरिक बेघर न हों, इसके लिए जरूरी है कि स्थानीय निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाए। अब असम के सीएम हमंता विश्वसरमा की बात, जिन्होंने हाल में कहा है कि भारत-चीन सीमा पर ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव 2-3 हजार क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड तक रहता है। वहीं जब ये नदी असम की समतल जमीन पर आती है, तो मानसून के दौरान इसका बहाव 15-20 हजार क्यूबिक मीटर प्रति

سے کنکن تک بढ़ جاتا है। उके मुताबिक, 'अगर चीन पानी का बहाव कम करता है, तो इससे असम में हर साल आने वाली बाढ़ को कंट्रोल करने में भारत को मदद मिलेगी। गौरतलब है कि भारत द्वारा पाकिस्तान का पानी रोकने के फैसले पर माना जा रहा है कि चीन इस मामले में बदले की कार्रवाई कर सकता है। हालांकि नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर प्रसेनजीत बिस्वास का कथन सामने आया है कि %भारत-चीन के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। दोनों ने कलाइमेट चेंज पर साथ आने का समझौता किया है। चीन नहीं चाहता है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी सूख जाए। दरअसल नदियां एक त्रिविंग सिस्टम से चलती हैं। यानी किसी भी नदी को जिंदा रखने के लिए भौगोलिक तौर पर ऊपर और नीचे पानी की तय मात्रा रखनी होती है। अगर पानी नीचे जाने से रोक दिया जाता है तो ऊपर भी नदी खट्टम हो जाएगी। मगर फिलहाल तो यह जरूरी है कि हर वर्ष बाढ़ की तबाही के खतरे वाले राज्यों में इससे निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की ठोस योजनाएं बनें।

# महत्वाकांक्षी PMFBY योजना में पहले की योजनाओं जैसी ही खामियां

■ कात पा. चिदबरम

भा रत के किसान दश का खाद्य सुरक्षा प्रदान करत ह लाकन खुद वे निरंतर कष्ट में रहते हैं। सरकार की नीतियों में उनकी उपेक्षा की जाती है। उनका योगदान महत्वपूर्ण होता है लेकिन वे वचित और बेजान बने रहते हैं। एक किसान परिवार से आए उपराश्वपति जगदीप धनकड़ि किसानों की शिकायतों को निरंतर सामने लाकर अपना असंतोष जाहिर करते रहे हैं। वे इस बात पर डोर देते रहे हैं कि किसानों की देखभाल करना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। कृषि देश की जीड़ीपी में हालांकि केवल 18.2 फीसदी का योगदान देती है लेकिन यह 42.3 फीसदी आवादी की आजीविका मुख्य स्रोत है। लेकिन पिछले एक दशक से भारत में कृषि क्षेत्र में रोजगार में बड़ी दशकीय गिरावट आई है। यह इस क्षेत्र की बड़ती कमजोरी का प्रमाण है। फसलों के नाकाम होने, कीमतों में गिरावट और बीमा के जरिए सुरक्षा देने के टूटे वादों की वजह से कृषि क्षेत्र का संकट एक महामारी जैसा बन गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के 2015 के आंकड़े बताते हैं कि किसानों द्वारा आत्महत्या के 80 फीसदी मामले कर्ज और दिवालियापान की वजह से हुए। इस संकट में बड़तरी ही होती दिखाई है। दिसंबर 2023 में एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में काम करने वाले 1,12,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (एनएसओ) द्वारा 2018 में किए गए एक सर्वे में पाया गया कि भारत में 50 फीसदी से ज्यादा खेतिहार परिवार कर्ज के बोझ से दबे थे। 2016 में शुरू की गई 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (पीएमएफबीवई) में फसल की बीम का वादा किया गया था, जिससे किसानों के मन में भरोसा जगा था। कागज पर तो इस योजना में पिछली कई खामियों को दूर कर दिया गया था लेकिन ध्यान से देखने पर जाहिर हुआ कि इस महत्वाकांक्षी बीमा योजना में भी पिछली योजनाओं की कई खामियां मौजूद थीं। यह योजना खेतिहार समृद्धाय की अपेक्षाओं को तो पूरा नहीं ही करती थी, जिन लोगों को सुरक्षा देने के लिए इसे लागू किया गया था उनको ही इसने अलगाथलग कर दिया। इसकी एक बुनियादी खामी दावों के निबटारे की अपेक्षा, जटिल, और बेंद तकनीकी किस्म की प्रक्रिया है। उपग्रह चित्र और विशाल यूनिटों के 'एवरेजिंग डाटा' के प्रयोग ने जमीनी हकीकत से कटी हुई व्यवस्था का निर्माण कर दिया। अहम बात यह है कि उपग्रह के जरिए जांच का दायरा सीमित है, इसमें केवल यह पता लगता है कि फसल लगी है या नहीं लगी है। इससे फसलों के बीच भेद भी नहीं किया जा सकता। यह तकनीकी खामी के कारण मुआवजे का गलत आधार तय होता है, जो वास्तविक आजीविका को नुकसान पहुंचाता है। कीड़ों के कारण किसानों को जो भारी नुकसान होता है या फसल की पौष्टिकता घटती है उसका मुआवजा उन्हें नहीं मिलता क्योंकि उपग्रह के चित्र में फसल हरी-भरी नजर आती है। इससे भी ज्यादा भायावह बात इस मॉडल में निहित असमानता का तत्व है। किसान व्यक्तिगत रूप से किस्त जमा करते हैं लेकिन मुआवजा गांव के अंदर के झामुटों या बड़ी और छोटी काशतों के बड़े अस्पष्ट इलाकों के आधार पर तय किया जाता है जिसमें यूनिटों का



क निबटार में दरा का जाता है या उन्ह खारज कर दिया जाता है जबकि निजी कंपनियां जोखिम मुक्त किस्तों की उगाही करती हैं। इस बीच, फसल कटाई के प्रयोग अपर्याप्त मजदूरों, खराब किस्म के कंट्रोल किया जाता है, और इन्स्प्रेक्ट्रर में खामी तथा जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण की कमी के कारण ड्रोन तथा एआर आधारित विश्लेषण जैसे तकनीकी उपायों का अध्यूगा इस्तेमाल होता है। सबसे चेतावनी वाली बात यह है कि सीएजी की 2022 की रिपोर्ट कहती है कि सर्वे में शामिल 37 फीसदी किसानों को ही प्रधानमंत्री फसल बीमा के लाभों, किस्तों के ढाँचे या दावा निबटारे की प्रक्रिया के बारे में वास्तविक जानकारी थी। जमीनी वास्तविकताएँ फसल बीमा की गंभीर खामियों को उजागर करती हैं। जबरन सदस्यता, दावों के निबटारे में देरी या उन्हें खारिज किया जाना और दोषपूर्ण सर्वे के कारण किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है और वे कर्ज से दबे रहते हैं। तमिलनाडु के मथिलादुशुराई जिला के कुल 277 गांवों में से केवल 68 गांवों को ही 2024 में फसल बीमा दावों की सुविधा हासिल थी और उनमें से केवल 16 गांवों को मुआवजा मिला था। दूसरे जिलों का भी यही हाल था। तमिलनाडु के 55 वर्षीय किसान डी। आरोग्यम ने कोई कर्ज नहीं लिया था लेकिन अधिकारियों ने उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जबरन शामिल होने को मजबूर किया। वे समय पर किस्तें भरते रहे लेकिन सूखे के कारण लगातार दो साल फसल खराब होने के बावजूद उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला और वे कर्ज लेने को मजबूर हुए। 'डाउन टू अर्थ' पत्रिका की खबर के मुताबिक, हरियाणा में सोनीपत के रोशन लाल ने बीमा करवाने की कभी सहमति नहीं दी थी फिर भी उन्हें यह धमकी देकर किस्त भरने को

मजबूर किया गया कि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें कर्ज के ब्याज पर मिलने वाली छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन जब उनकी फसल खराब हो गई तो ‘तकनीकी कारणों’ से उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया और उन्हें बीमा वे कागजात कभी दिखाए नहीं गए। राजस्थान में कई किसानों के दावे इसलिए निरस्त हो गए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उनकी किस्तों को दर्ज नहीं किया। इसलिए उन्होंने अपेक्षित भुगतान की उम्मीद किए बिना अगली फसल लगाई। तमिलनाडु के किसानों को मौसम की गड़बड़ियों को अक्सर झेलना पड़ता है। दूसरे राज्य तो दक्षिण-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी मॉनसून पर निर्भर करते हैं लेकिन तमिलनाडु उत्तर-पूर्वी मॉनसून पर ही निर्भर करता है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण काफी अनिश्चित रहता है। ‘इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैफिकल मेटियरलॉजी’ के 2023 के एक सर्वे में पाया गया कि पिछले दशक में बादल फटने और कहीं-कहीं बाढ़ आ जाने की घटनाओं में वृद्धि के बावजूद उत्तर-पूर्वी मॉनसून की बारिश में 15 फीसदी की कमी आई है। उदाहरण के लिए तंजावुर, तिरुवरुर, पुदुचेरी और नागपट्टम जैसे टटीय इलाकों में 2022-2023 के एक ही फसल सीज में कमी देर से तो कमी बेमौसम बारिश हुई। लेकिन किसानों की आय में कमी की भरावाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत तब तक नहीं की जाती जब तक इलाके की औसत पैदावार ‘कट-ऑफ’ सीमा से नीचे नहीं जाती, और यह व्यक्तिगत मुआवजे को खारिज कर देती है। फसलों का आकलन जीपीएस एप और उपग्रह चित्रों के आधार पर किया जाना चाहिए और फसलों की निगरानी में एआई का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

‘ब्लॉकचेन’ से किसानों की पहचान की जा सकती है और सबको जोड़ा जा सकता है। खुले मंचों और मोबाइल के जरिए हासिल सूचनाओं की मदद से जवाबदेही तय की जा सकती है। डोन, सेसर, और प्रशिक्षण की मदद से डिजिटल खाइ को पाटा जा सकता है। पंचायतें व्हाइस आधारित हेल्पलाइन की मदद से स्थानीय लोगों को आधुनिक टेक्नोलॉजी की शिक्षा दे सकती हैं। मैं ‘डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ (डीबीटी) जैसे सबसे महत्वपूर्ण उपायों का पूरा समर्थन करता हूं, यह व्यवस्था किसी बिचौलीए, किसी जटिलता और अपारदर्शी नौकरशाही प्रक्रियाओं में उलझे बिना सीधे लाभार्थी को लाभ पहुंचाती है। हाल में, इसकी इसी की पुष्टि करते हुए उपराष्ट्रित ने अप्रत्यक्ष सब्सीडी की खामियों को रोखाकित करते हुए कहा कि: “इसमें ‘लीकेज’ की हमेशा ऊंजाइश रहती है, इससे अधिकतम परिणाम नहीं मिलते।” प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे कार्यक्रम भारत की कृषि नीति में ढांचागत दरारें और वित्तीय खामियों को उत्तापन करते हुए सुधारों की जरूरत पर डोर देती हैं। जलवायु और कृषि संबंधी संकटों से निपटने के लिए इस योजना को पारदर्शी, जवाबदेह, और संबंदेनशील सहायता व्यवस्था बनाने की जरूरत है जो किसानों को डाटा न मान कर मनुष्य माने जिनकी आजीविका उनके दावों की समय पर तथा मानवीय निबटारे पर आधारित हो। खेती सिर्फ आर्थिक गतिविधि नहीं है, यह एक जीवन शैली है जिसे ऐसी शासन व्यवस्था की जरूरत है जो किसानों की बात सुनती हो, समझती हो और सच्चे सरोकार के साथ काम करती हो।

THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES

બાજ ફા ઇતિહાસ

- 1720 भ्राता द्वारा इंडिया कंपनी को हस्ताक्षर किये।
  - 1674 शिवाजी, जिन्होंने बीजापुर और मुगल साम्राज्य के सलतनत से मुक्त करने के लिए प्रतिरोध का नेतृत्व किया, जो मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति का ताज पहनाया गया।
  - 1744 फ्रांस और पर्शिया ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किया।
  - 1761 शुक्र का पारगमन हुआ जिसे पृथ्वी के 120 स्थानों से देखा जाता है। मिखाइल लोमेनोसोव को वीनस का माहौल पता चला।
  - 1808 नेपोलियन के भाई जोसफ को स्पेन का राजा बनाया गया था।
  - 1813 ग्रेगरी ब्लैन्कमैलेंड, विलियम लॉसन और विलियम वेंटवर्थ ब्लू माउंटेनों को पार करके घर लौटकर बापिस आ गए।
  - 1813-1812 का युद्ध-ब्रिटिश ने ओटोरियो के स्टोइन ऋकी के पास अमेरिकी दबंग पर हमला किया, दो वरिष्ठ अधिकारियों को पकड़ लिया।
  - 1844 लंदन में युवा पुरुष ईसाई संघ (वाईएमसीए) की स्थापना की गयी।
  - 1844 वाईएमसीए, आज 124 राष्ट्रीय महासंघों के 45 मिलियन से अधिक सदस्यों के विश्वव्यापी आंदोलन की स्थापना लंदन में हुई थी।
  - 1859 क्रीन विकटोरिया ने न्यू साउथ वेल्स से क्यूक्यून्सलैंड की कॉलोनी को अलग करने वाले पत्रों पर हस्ताक्षर किए।
  - 1862 मेम्फिस की पहली लड़ाई में अमेरिकी नागरिक युद्ध-संघ की सेना की जीत ने मिसिसिपी नदी पर कॉन्फेडरेट नौसेना की उपस्थिति को लगभग समाप्त कर दिया।
  - 1882 न्यूयॉर्क के हेनरी डब्ल्यू सिले ने इलेक्ट्रिक आयरन का पेटेंट लिया।
  - 1882 शेवा साम्राज्य ने गोजाम को हराकर और गिबे नदी के दक्षिण में धमनियों पर नियंत्रण हासिल करके इथियोपियाई साम्राज्य पर आधिपत्य हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया।
  - 1892 शिकागो के %एल% ट्रेन (1922 ट्रेन का चित्र), यूनाइटेडस्टेट्स में कुल ट्रैक माइलेज में दूसरा सबसे लंबा रैपिड ट्रैकिट सिस्टम, संचालन शुरू हुआ।
  - 1894 कोलोराडो के गवर्नर डेविस हैन्सन वेइट ने अपने राज्य मिलिशिया को क्रिप्पल ऋकी माइनर्सस्ट्राइक में लगे खनिकों की रक्षा और समर्थन करने का आदेश दिया।

# बढ़ता प्लास्टिक प्रदूषण दुनिया की जटिल पर्यावरण समस्या

ललित गर्ज

**ब**ढ़ता तापमान, बदलत जलवायु एवं ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से ग्लेशियर तेरी से पिघल कर समुद्र का जलस्तर तीव्रताति से बढ़ा रहे हैं। जिससे समुद्र किनारे बसे अनेक नगरों एवं महानगरों के डूबने का खतरा मंडराने लगा है। इंसानों को प्रकृति, पृथ्वी एवं पर्यावरण के प्रति सचेत करने के लिये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जो पर्यावरण, प्रकृति एवं पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोज्य यह दिवस दुनिया भर के लाखों लोगों को हमारे ग्रह की सुरक्षा और पुनर्स्थापना के साझा मिशन के साथ एक जुट करता है। बड़ता प्लास्टिक प्रदूषण दुनिया की एक गंभीर एवं जटिल समस्या है, इसीलिये 2025 में इस दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर केंद्रित है। कोरिया गणराज्य वैश्विक समारोह की मेडबानी करेगा। दशकों से प्लास्टिक प्रदूषण दुनिया के हर कोने में फैल चुका है, यह हमारे पीने के पानी, हमारे खाने, हमारे शरीर, हमारे पर्यावरण में समा रहा है। इस प्लास्टिक कचरे की गंभीर समस्या से निपटने का एक वैश्विक संकल्प निश्चित ही एक समाधान की दिशा बनेगा। हर साल 430 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से लगभग दो-तिहाई केवल एक बार उपयोग के लिए होता है और जल्दी ही फेंक दिया जाता है।



पुहुचाया है, जिसके कारण न केवल नाद्या, बन, रेगिस्तान, जलस्रोत सिकुड़ रहे हैं बल्कि ग्लोशियर भी पिघल रहे हैं, तापमान का 50 डिग्री पार करना जो विनाश का संकेत तो है ही, जिससे मानव जीवन भी असुरक्षित होता जा रहा है। इन वर्षों में बड़ी हुई गर्मी एवं तापमान ने न केवल जीवन को जटिल बनाया बल्कि अनेक लोगों की जान भी गयी। पूरी दुनिया में बड़ता प्लास्टिक प्रदूषण, जलवायु उरारजकता और जैव विविधता विनाश का एक जहरीला मिश्रण स्वस्थ भूमि को रेगिस्तान में बदल रहा है, संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मृत क्षेत्रों में बदल रहा है और मानव जीवन पर तरह-तरह के खतरे पैदा कर रहा है।

प्रकृति को पस्त करने, वायु एवं जल प्रदूषण, कृषि संसाधनों पर वायरल संकरण, जलवायु बदलने के लिए

फसलों पर घातक प्रभाव, मानव जीवन एवं जीव-जन्तुओं के लिये जानलेवा साबित होने के कारण समूची दुनिया में बड़ते प्लास्टिक एवं माइक्रोप्लास्टिक के कण एक बड़ी चुनौती एवं संकट है। पिछले दिनों एक अध्ययन में मनुष्य के मस्तिष्क में प्लास्टिक के नैनो कणों के पहुंचने पर चिंता जातियों गई थी। दावा था कि प्रतिदिन सैकड़ों माइक्रोप्लास्टिक कण सांसों के जरिये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे तमाम नये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय शोध-सर्वेक्षण-अध्ययन चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी सांसों, प्रकृति, पर्यावरण, पेयजल व फसलों में घातक माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी एक गंभीर संकट है। संकट तो यहां तक बढ़ गया है कि प्लास्टिक के कण पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने लगे हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला में शामिल कई खाद्यान्नों की उत्पादकता में गिरावट आ रही है। ऐसा निष्कर्ष

साझा अध्ययन के बाद समन आया हा।  
दरअसल, प्लास्टिक कणों के हस्तक्षेप  
के चलते पौधों के भोजन सुजन की  
प्रक्रिया बाधित हो रही है। इस तरह  
माइक्रोलास्टिक की दखल भोजन,  
हवा व पानी में होना न केवल प्रकृति,  
कृषि, पर्यावरण वरन् मानव अस्तित्व  
के लिये गंभीर खतरे की धंटी ही है।  
जिसे बेहद गंभीरता से लिया जाना  
चाहिए और सरकारों को इस संकट से  
एं उद्घाटित करने के लिये योजनाएं बनानी  
लिये इस वर्ष की थीम से व्यापक बदलाव  
हैं।

प्लास्टिक हमारे बातावरण का एक हिस्सा नास्टिक की बहुलता एवं निर्भरता के द्वारा सामने मंडरा रही है। हम चाहकर भी जीवन की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, जिन के खतरों को देखते हुए विभिन्न देशों ने ठान लिया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्तर नहीं होगी। भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश को स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसे मुक्त करने की अपील करते हुए एक शुभारंभ कर चुके हैं। प्लास्टिक के कारण निया में विभिन्न तरह की समस्याएँ पैदा हो गईं खतरे दो तरह के हैं। एक तो से बहुत से रसायन होते हैं, जो कैंसर का तोते हैं। इसके अलावा शरीर में ऐसी चीज़ें हैं जो हजाम करने के लिए हमारा शरीर बना ही नहीं सकता ऐसे देशों ने एक नियम लाया है कि

कइ तरह से सहत का जाटिलाए पेदा कर  
आम लोगों का ही इससे मुक्ति का  
होगा, जागृति लानी होगी।  
अों ने केलन में दस प्रमुख ब्रांडों के  
तो अध्ययन का विषय बनाया है।  
प्रक्षर्ष है कि प्लास्टिक की बोतल के पानी  
नरें वाले व्यक्ति के शरीर में प्रतिवर्ष 153  
कण प्रवेश कर जाते हैं। पिछ्ली सदी में  
के विभिन्न रूपों का अविष्कार हुआ, तो  
र मानव सभ्यता की बहुत बड़ी उपलब्धि

पा रह ह आर न इसका उपयोग हार का पा रह ह, ता क्या न इसे विज्ञान और मानव सभ्यता की सबसे बड़ी असफलता एवं त्रासदी मान लिया जाएँड अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने यहां बारिश के पानी के नमूने जमा किए। ये नमूने सीधे आसमान से गिरे पानी के थे, बारिश की वजह से सड़कों या खेतों में बह रहे पानी के नहीं। जब इस पानी का विश्लेषण हुआ, तो पता चला कि लगभग 90 फीटसदी नमूनों में प्लास्टिक के बारिक कण या रेशे थे, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। ये इतने स्मृक्ष होते हैं कि हम इन्हें आँखों से नहीं देख पाते। लगातार पांव पसार रही माइक्रोप्लास्टिक की तबाही इंसानी गफलत को उजागर तो करती रही है, लेकिन समाधान का कोई रास्ता प्रस्तुत नहीं कर पाई। ऐसे में अगर विश्व पर्यावरण दिवस पर प्लास्टिक के संकट का दूर करने की कुछ ठानी है तो उसका स्वागत होना ही चाहिए। प्लास्टिक प्रदूषण की उससे भी ज्यादा खतरनाक एवं जानलेवा स्थिति है, यह एक ऐसी समस्या बनकर उभर रही है, जिससे निपटना अब भी तुनिया के ज्यादातर देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। कुछ समय पहले एक खबर ऐसी भी आई थी कि एक चिड़ियाघर के दरियाई घोड़े का निधन हुआ, तो उसका पोस्टमार्टम करना पड़ा, जिसमें उसके पेट से भारी मात्रा में प्लास्टिक की थैलियां मिलीं, जो शायद उसने भोजन के साथ ही निगल ली थीं। कनार्डाई वैज्ञानिकों द्वारा माइक्रोप्लास्टिक कणों पर किए गए विश्लेषण में चौंकाने वाले नतीजे मिले हैं। विश्लेषण में पता चला है कि एक वयस्क पुरुष प्रतिवर्ष लगभग 52000 माइक्रोप्लास्टिक कण के बल पानी और भोजन के साथ निगल रहा है। इसमें अगर बायु प्रदूषण को भी मिला दें तो हर साल करीब 1,21,000 माइक्रोप्लास्टिक कण खाने-पानी और सांस के जरिए एक वयस्क पुरुष के शरीर में जा रहे हैं। अमेजन एवं फिलीपार्ट जैसे आनलाइन व्यवसायी प्रतिदिन 7 हजार किलो प्लास्टिक पैकेजिंग बैग का उपयोग के बल भारत में करते हैं। इन कम्पनियों को भी प्लास्टिकमुक्त दुनिया के घेरे में लेने के लिये कठोर कदम उठाने चाहिए। संकट का एक पहलू यह भी है कि लोग सुविधा को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन प्लास्टिक के दूरगामी घातक प्रभावों को लेकर आंख मूँद लेते हैं।

- साभार







